आकाशवाणी जयपुर–अजमेर

दिनांकः 10.07.2024 समय : 01:00 पी.एम.

- **उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट किया पेश–राजस्थान को साढ़े तीन सौ बिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाने का लक्ष्य।**
- **अगले पांच सालों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प–इस साल एक लाख भर्तियां करने की घोषणा।**
- **राज्य में अगले साल से अलग से ग्रीन बजट होगा पेश–हरित राजस्थान बनाने के लिए मिशन हरियालो राजस्थान होगा शुरू।**
- **प्रदेश में किसानों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के बजट की घोषणा और 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य।**

00000

उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024–25 के राज्य बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क विकास और खेल सहित अन्य क्षेत्रों को लेकर विभिन्न घोषणाएं की हैं। वित्तमंत्री ने आज 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को साढे तीन सौ बिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनता से किये वादों को धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया है। विकसित राजस्थान–2047 के लक्ष्य के साथ पांच साल की कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें भविष्य के लिए दस संकल्प रखे गये हैं।

.....

वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच सालों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस साल के लिए भर्तियों का लक्ष्य 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने की घोषणा की।

.....

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रदेश में छह नई जल परियोजनाओं का ऐलान करते हुए कहा कि ईआरसीपी के पहले चरण का काम शुरू हो चुका है। पांच हजार 846 गांवों में पांच हजार करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाएं लाई जाएंगी। 32 वॉटर बॉडीज़ का जीर्णोद्धार होगा और हर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपम्प लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली की बढ़ती मांग और विद्युत तंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उत्पादन क्षेत्र की कार्य योजना तैयार की गई है। ऊर्जा भंडारण के लिए नई नीति लाई जाएगी। कुसुम योजना के तहत तीन हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। वर्ष 2031–32 तक बिजली मांग की पूर्ति के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। आगे आने वाले दिनों में 2 लाख घरों में बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे।

राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट में 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का करीब सवा आठ प्रतिशत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती देने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक–एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किये जाएंगे। मुख्यमंत्री मां स्वास्थ्य मिशन के तहत 15 हजार करोड़ रुपये के काम करवाए जाएंगे। आने वाले समय में राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन शुरू किया जाएगा। इससे ऑनलाइन चिकित्सा के साथ ही मरीजों का डेटा भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। दुर्लभ बीमारियों के निदान के लिए 50 करोड़ रुपये का अलग से फंड बनाया जाएगा। डॉक्टरों के डेढ हजार और नर्सिंगकर्मियों के चार हजार नए पद सृजित किये जाएंगे। पुलिस विभाग में साढे पांच हजार नए पद बनाए जाएंगे। अगले साल से राज्य में अलग से ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। हरित राजस्थान के उद्देश्य को साकार करने के लिए **मिशन हरियालो राजस्थान** शुरू होगा। इस पर पांच सालों में चार हजार करोड़ रुपये खर्च कर विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। 2 हजार स्थानीय नागरिकों को वन मित्र लगाया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

.....

अलग से पेश किये गये कृषि बजट में किसानों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों में दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति करने की घोषणा की गयी। मार्च 2024 तक के लंबित विद्युत कनेक्शन जल्द जारी किये जाएंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक एंड कनवेंशनल फार्मिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। पांच हजार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। ईआरसीपी परियोजना को रामगढ़ बांध से जोड़ने के लिए 9 हजार 600 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का ऐलान किया गया है। बजट भाषण में कई कर प्रस्ताव भी रखें गये। वित्त मंत्री ने कहा की राज्य में उद्यमिता,

निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एमनेस्टी योजनाएं प्रस्तावित की जा रही है जो 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। वेट एमनेस्टी के तहत अन्तरराज्यीय बिक्री के मामलों, लंबित और विवादित मामलों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जायेगी। स्टाम्प ड्यूटी की मांग के मामलों में ब्याज और पेनल्टी की शत प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के उद्यमियों और निवेशकों की कानूनी और वित्तीय समस्याओं का समाधान करने और उन्हें राहत देने की दृष्टि से लैण्ड टैक्स समाप्त करने की घोषणा की। इनके अलावा आज हुई अन्य बजट घोषणाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ढाई प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओ का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए शुरू की गयी लखपति दीदी योजना के तहत 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 14 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं के लिए विभिन्न स्थानों पनर 67 पिंक बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि दो हजार निशक्तजन को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन पचास हजार रुपये से बढाकर साठ हजार रुपये करना प्रस्तावित है। प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा। चयनित युवाओं को दस करोड़ रुपये की फंडिंग सुविधा का प्रावधान किया गया है। छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए मैस भत्ता तीन हजार रुपये किये जाने का ऐलान हुआ। 50 नए प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। वहीं हर संभाग में बालिका सैनिक स्कूल शुरू किये जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच–पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे। दो हजार आंगनबाडी केन्द्रों के उन्नयन पर 40 करोड रुपये का खर्च प्रस्तावित है। जनजाति क्षेत्रों में ढाई सौ नए मां–बाड़ी केन्द्र खोले जाएंगे।

एक अप्रैल 2024 के बाद कर्मचारी हित की ग्रेच्यूटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अल्ट्रा फिटनेस सेंटर बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। जयपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में नई पर्यटन नीति लाई जाएगी। प्रसिद्ध खाटू धाम के विकास के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विभिन्न अभ्यारण्यों में ईको टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रवासी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। रोडवेज बेड़े में पांच सौ नई बसें और तीन सौ इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। रोड़वेज में एक हजार 650 पदों पर नई भर्तियां होंगी। 2 हजार 750 किलोमीटर लम्बे नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। हर संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क स्क्वाड गठित की जाएगी। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के बाद त्वरित मदद के उद्देश्य से 25 लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस लगाई जाएंगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हैलीपेड का निर्माण किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में युवा वर्ग को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए बड़े पैमाने पर स्किल अपग्रेडेशन होगा। साथ ही इस साल नई युवा नीति लाई जाएगी। राज्य सरकार यूथ आइकन भी प्रदान करेगी। खेलो राजस्थान यूथ गेम का आयोजन होगा। खेलों के बजट को दो गुना किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं में बढते नशा प्रवृति को लेकर नए नशा मुक्ति केन्द्र खोले जाएंगे। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। अधिस्वीकृत पत्रकारों के आरजीएचएस सुविधा का लाभ मिलेगा। वित्तमंत्री ने सदन में बजट भाषण की शुरूआत अंतरिम बजट में जनता के लिए की गई घोषणाओं के जिक्र से की।

0000